साप्ताहिक
जागत गांव हमार
पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक
RNI-MPHIN/2015/72544
चौपाल से भोपाल तक
भोपाल, सोमवार 01-07 मई, 2023, वर्ष-9, अंक-03
भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित
पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

शिवराज कैबिनेट का फैसला | सरकार ने फसल क्षतिपूर्ति की राशि बढ़ाई

» कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने की योजना समेत अन्य प्रस्तावों पर मुहर

देश में सबसे ज्यादा फसल मुआवजा देने वाला राज्य मप्र

» 25 से 33 प्रतिशत फसल क्षति होने पर 5 हजार 500 रुपए

» 33 से 50 प्रतिशत फसल क्षति होने पर 8 हजार 500 रुपए

» 50 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति होने पर 17 हजार रुपए

» प्रति हेक्टेयर 25 से 33 प्रतिशत फसल क्षति होने पर 9 हजार 500 रुपए

» 33 से 50 प्रतिशत फसल क्षति होने पर 16 हजार

» 25 से 33 प्रतिशत फसल क्षति होने पर) फसल के लिए 9 हजार 500 रुपए

» 33 से 50 प्रतिशत फसल क्षति होने पर 19 हजार

» 50 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति होने पर 32 हजार रुपए

भोपाल। जागत गांव हमार

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्राकृतिक आपदा के कारण फसल खराब होने पर किसानों को दी जाने वाली राहत राशि में वृद्धि के निर्णय का अनुसमर्थन किया गया। राजस्व विभाग के अंतर्गत आरबीसी 6/4 में संशोधन किया है। जिसके बाद मप्र अब देश में सबसे ज्यादा फसल मुआवजा देने वाला राज्य बन गया है। बढ़ा मुआवजा 1 मार्च 2023 के बाद से खराब होने वाली फसलों के लिए दिया जाएगा। प्रदेश में 45 नए दीनदयाल रसोई केंद्र प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए योजना की स्वीकृति दी गई। इसमें किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए सरसों, चना, बासमती चावल, कोदो और कुटकी को चुना गया है। पन्ना जिले में दो सिंचाई परियोजनाओं की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई।

25 से 33 फीसदी फसल के नुकसान पर

कैबिनेट की बैठक में तय किया गया कि वर्षा आधारित फसल के लिए 5500 रुपए प्रति हेक्टेयर, सिंचित फसल के लिए 9500 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा दिया जाएगा। बारहमासी 9500 रुपए प्रति हेक्टेयर, बारहमासी 16,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मदद राशि दी जाएगी। सब्जी, मसाले, ईसबगोल की खेती के लिए 19,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा दिया जाएगा।

33 से 50 फीसदी फसल के नुकसान पर

वर्षा आधारित फसल के लिए 8500 रुपए प्रति हेक्टेयर, सिंचित फसल के लिए 16,500 रुपए प्रति हेक्टेयर। बारहमासी 19,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, बारहमासी 21,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। सब्जी, मसाले, ईसबगोल की खेती के लिए 27000 रुपए प्रति हेक्टेयर, सेरीकल्चर के लिए 6,500 रुपए प्रति हेक्टेयर, मूंगा के लिए 8,000 रुपए हेक्टेयर मुआवजा दिया जाएगा।

50 फीसदी से अधिक फसल के नुकसान पर

वर्षा आधारित फसल के लिए 17,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, सिंचित फसल के लिए 32,000 रुपए प्रति हेक्टेयर। बारहमासी 32,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, बारहमासी 32,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, सब्जी, मसाले, ईसबगोल की खेती के लिए 32,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, सेरीकल्चर फसल के लिए 13,000 रुपए हेक्टेयर और मूंगा के लिए 16,000 रुपए हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा।

सिंचित फसल

» 25 से 33 प्रतिशत फसल क्षति होने पर 7 हजार रुपए

» 33 से 50 प्रतिशत फसल क्षति पर 14 हजार 500 रुपए

» 50 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति पर 29 हजार रुपए

बारामाही फसल

» 25 से 33 प्रतिशत फसल क्षति होने पर) फसल के लिए 13 हजार रुपए

» 33 से 50 प्रतिशत फसल क्षति होने पर 19 हजार रुपए

» 50 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति होने पर 32 हजार रुपए

सब्जी की खेती

» 25 से 33 प्रतिशत फसल क्षति होने पर 15 हजार रुपए

» 33 से 50 प्रतिशत फसल क्षति होने पर 19 हजार रुपए

» 50 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति होने पर 32 हजार रुपए

38 हजार किसानों को हुआ है नुकसान

मार्च में मध्यप्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई है जिससे फसलों को काफी नुकसान हुआ है। बीते महीने हुई बारिश में करीब 38 हजार किसानों को नुकसान झेलना पड़ा है। कई ऐसे किसान हैं जिनकी 30 हजार हेक्टेयर से अधिक की फसल नष्ट हो गई। इस दौरान गेहूं, सरसों और आलू की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है।

आहत किसानों को राहत: सागर जिले को अधिक 26 करोड़

इधर, सरकार ने ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से खराब हुई रबी फसलों के नुकसान की राहत राशि का वितरण किया। 36 जिलों के 1 लाख 48 हजार किसानों के खातों में मुख्यमंत्री ने 159 करोड़ 52 लाख सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर किए। सबसे ज्यादा राहत राशि सागर जिले में 26.50 करोड़ किसानों को ट्रांसफर की गई। निवाड़ी के किसानों को 19 करोड़ और दतिया, शिवपुरी और छतरपुर के किसानों के खाते में 12-12 करोड़ समेत अन्य जिलों के किसानों के खातों में राशि का वितरण किया गया। सरकार किसानों को फसल कटाई प्रयोग के आधार पर फसल बीमा योजना का लाभ भी दिलाएंगी। सरकार ने बारिश से फसलों को नुकसान होने से प्रभावित किसानों से कर्ज वसूली स्थगित की है। ऐसे किसानों के घर बेटी की शादी होने पर 55 हजार की सरकार अलग से मदद करेगी।

मध्य प्रदेश में भी लक्ष्य की 50 प्रतिशत खरीदी पूरी

गेहूं की सरकारी खरीदी में तेजी 17 मिलियन टन के पार आंकड़ा

भोपाल। एमएसपी पर गेहूं की सरकारी खरीदी में अब तेजी आ रही है। बीते वर्ष कमजोर खरीदी के बाद इस साल अब सरकार राहत की सांस ले सकती है। 24 अप्रैल तक के जारी आंकड़ों के अनुसार देशभर में कुल 17.08 मिलियन टन से ज्यादा गेहूं खरीदा जा चुका है। इस सीजन में सरकार ने कुल खरीदी लक्ष्य 34.15 मिलियन टन रखा है। यानी लक्ष्य का आधा हासिल कर लिया है। इस सीजन में अंतिम समय पर मौसम के बदले मिजाज के कारण गेहूं की आवक देर से हुई। खरीदी भी देरी से शुरू हो सकी। सरकार के लिए राहत वाली बात है कि अब वह पीडीएस में अनाज वितरण को लेकर निश्चिंत रह सकती है। अब उम्मीद की जा रही है कि खरीद का लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है। 2125 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकार ने इस खरीदी के लिए 36 हजार 301 करोड़ रुपए का भुगतान किया है।

सरकारी खरीद में मप्र का सबसे बेहतर प्रदर्शन

सरकारी खरीद में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन सबसे बेहतर है। प्रदेश में 4.29 मिलियन टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। लक्ष्य 8 मिलियन टन का है। प्रदेश में खरीद में बीते साल से 66 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हरियाणा और उप्र में भी वृद्धि है लेकिन पंजाब में कमी आती दिखी है। इससे पहले सेंट्रल पूल में गेहूं की कमी के कारण बीते वर्ष 10 राज्यों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कोटा कम कर दिया था। अब गेहूं की खरीदी पूरी होने के बाद इस महीने के आखिर तक केंद्र वितरण प्रणाली के कोटे की समीक्षा कर बहाली कर सकता है।

कलेक्टरों से पंचायतों के प्रस्ताव मांगे, पंचायतों को दिया जाएगा पुरस्कार

लाड़ली लक्ष्मी फ्रेंडली होंगी ग्राम पंचायत

भोपाल। जागत गांव हमार

राज्य सरकार ग्राम पंचायतों को लाड़ली लक्ष्मी फ्रेंडली घोषित करेगी। इसके लिए कलेक्टरों से ऐसी पंचायतों के प्रस्ताव मांगे गए हैं, जिनमें पिछले एक वर्ष में एक भी बाल विवाह नहीं हुआ हो। सौ प्रतिशत लाड़ली लक्ष्मी स्कूल जाती हों और उनका टीकाकरण भी किया गया हो। पंचायत में कुपोषण न हो और पंचायत क्षेत्र में बालिकाओं के विरुद्ध कोई अपराध घटित न हुआ हो। ऐसी पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा। लाड़ली लक्ष्मी फ्रेंडली पंचायतों को बेटियों की सुरक्षा, उनके सर्वांगीण विकास के लिए अलग से बजट देने का प्राविधान भी किया जा रहा है। लाड़ली लक्ष्मी फ्रेंडली पंचायत घोषित करने के लिए पंचायतों से ही प्रस्ताव लिए जाएंगे। जिन्हें जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स के समक्ष रखा जाएगा। समिति गुणदोष के आधार पर पंचायतों को लाड़ली लक्ष्मी फ्रेंडली घोषित करेगी। बता दें कि टास्क फोर्स बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत गठित है।

लिंगानुपात की समीक्षा की जाएगी

लाड़ली लक्ष्मी फ्रेंडली पंचायत घोषित करने से पहले जिले में पंचायतवार वर्तमान लिंगानुपात की समीक्षा की जाएगी, जो प्रत्येक तीन माह में होगी। लिंगानुपात में पिछले साल की अपेक्षा सुधार करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा। पंचायतों में बेटी के जन्म पर उत्सव मनाया जाएगा, बाल विवाह के बारे में जागरुक किया जाएगा।

समय पर कार्य पूरा नहीं करने पर ब्लैक लिस्ट होगी लापरवाह निर्माण एजेंसी

मुख्यमंत्री ने की नर्मदा घाटी विकास विभाग की समीक्षा

सिंचाई परियोजनाओं के कार्य में विलम्ब बर्दाशत नहीं होगा

भोपाल। जागत गांव हमार

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नर्मदा घाटी विकास विभाग अंतर्गत निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं का कार्य जल्द पूरा कर लोकार्पण की तैयारी की जाए। कार्य में गुणवत्ता और समय-सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री ने परियोजनावार समीक्षा कर जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं का कार्य पूर्ण करने में विलम्ब न हो। समय पर कार्य पूरा नहीं करने वाली निर्माण एजेंसियों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। निर्माण एजेन्सियों को तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए जाए। परियोजनाओं का कार्य मिल-जुल कर समय पर पूरा करें। प्रदेश की यह महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, जो जनता की जिंदगी और कल्याण से जुड़ी हुई हैं। मुख्यमंत्री मंत्रालय में नर्मदा घाटी विकास विभाग की सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाह, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव जल संसाधन एवं वाइस चेयरमेन एनव्हीडीए एसएन मिश्रा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। संबंधित जिलों के कलेक्टर वर्चुअली जुड़े।

कार्य में देरी मुख्यमंत्री ने व्यक्त की नाराजगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि बदनावर माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना को गंभीरता से पूरा करने की कोशिश करें। उन्होंने परियोजना के कार्य में विलम्ब होने पर अप्रसन्नता व्यक्त की। मुख्यमंत्री चौहान ने संतोष व्यक्त किया कि सांवेर माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का कार्य समय पर चल रहा है। नर्मदा-क्षिप्रा बहुउद्देश्यीय परियोजना का जून में लोकार्पण कराया जाए। परियोजनाओं के संबंध में कलेक्टर खरगोन और देवास से भी चर्चा की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इंदिरा सागर परियोजना काली सिंध सूक्ष्म उद्वहन परियोजना के प्रथम चरण का कार्य 25 सितम्बर तक पूरा किया जाए। कुक्षी माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना एवं पाटी उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना का कार्य तेजी से पूरा करें। लगभग पूर्ण नागल वाड़ी उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना की टेस्टिंग कर ली जाए।

निर्माण कार्य में तीन वर्ष की देरी पर नाराजगी

मुख्यमंत्री ने बलकवाड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना (फेज-1) के कार्य में 3 वर्ष की देरी होने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने निर्माण एजेंसी कल्पतरू पॉवर ट्रांसमिशन लिमिटेड को 30 जून तक कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण न होने पर ब्लेक लिस्ट करने की कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिपरी माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना, बिस्टान उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना और भीकनगांव बिन्जलवाड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का कार्य तेजी से पूरा करें। इन परियोजनाओं का कार्य हर हाल में जून 2023 तक पूरा किया जाए।

छीपानेर माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के कार्य में विलंब न हो

मुख्यमंत्री ने कहा कि जावर माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना, खालवा उद्वहन सिंचाई परियोजना के कार्य में देरी नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं छीपानेर माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के कार्य को देखने भी गया था। इस परियोजना के कार्य में विलम्ब न हो। उन्होंने निर्माण एजेंसी शापूर जी पालोन जी-पीसी-एपीएल (जेव्ही) मुम्बई को निर्देशित करते हुए कहा कि यदि शीघ्रता से कार्य नहीं हुआ तो ब्लेक लिस्ट करने की कार्रवाई होगी। नर्मदापुरम एवं छिंदवाड़ा जिले की दूधी परियोजना का कार्य समय पर चल रहा है। इसी तरह शंकर पेंच लिंक संयुक्त परियोजना का कार्य भी समय पर चल रहा है।

किसानों को किराए पर आसानी से मिलेगा कृषि यंत्र

किसानों को कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित

भोपाल। जागत गांव हमार

कृषकों को कृषि फसलों के लिए किराए पर ट्रैक्टर और यंत्र उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से बैंक ऋण आधार पर कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करने के इच्छुक व्यक्तियों से ऑन लाइन आवेदन पत्र संचालनालय, कृषि अभियांत्रिकी के पोर्टल www.chc.mpdage.org के माध्यम से आमंत्रित किए गए हैं। इसके नियम और शर्तें इस प्रकार हैं-

नियम और शर्तें- इसमें प्रत्येक कस्टम हायरिंग केंद्र हेतु आवश्यक ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्रों की क्रय की लागत (अधिकतम 25 लाख) पर सभी श्रेणी के आवेदकों को अधिकतम 10 लाख तक का क्रेडिट लिंकड बैंक एन्डेड अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ ही हितग्राही भारत सरकार के एग्रीकल्चर इफ्रास्ट्रक्चर फण्ड (एआई एफ) अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के भी पात्र होंगे। प्रदेश में कुल 455 कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित होंगे, जिनमें से सामान्य के 238 , अजजा के 61, अजा के 52, एसआरएलएम के कृषक समूहों के 52 तथा एफपीओ के 52 पद के लिए आमंत्रित किए जा रहे हैं। यदि किसी जिले में एफपीओ अथवा कृषक समूहों के आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं, तो इनके शेष लक्ष्यों को व्यक्तिगत श्रेणी के आवेदकों को स्थानांतरित किए जा सकेंगे। जिले अनुसार लक्ष्यों को कम करने या बढ़ाने का अधिकार संचालक, कृषि अभियांत्रिकी को रहेगा। प्राप्त आवेदन वित्तीय वर्ष 2023 -24 के लिए ही वैध रहेंगे।

धरोहर राशि और अंतिम तिथि

प्रत्येक आवेदक को आवेदन के लिए धरोहर राशि 10 हजार रुपए बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करानी होगी। ऑन लाइन आवेदन के साथ धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट की स्कैन प्रति अपलोड करनी होगी। भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग के सभी जिलों के आवेदक को अपना बैंक ड्राफ्ट सहायक कृषि यंत्री, भोपाल तथा इंदौर-उज्जैन संभाग के जिलों के आवेदकों को बैंक ड्राफ्ट सहायक यंत्री कृषि, इंदौर के नाम से बनाना होगा। इसी तरह रीवा और शहडोल संभाग के सभी जिले सहायक कृषि यंत्री, सतना, जबलपुर संभाग के सभी जिले सहायक कृषि यंत्री, जबलपुर, सागर संभाग के सभी जिले सहायक कृषि यंत्री ,सागर तथा ग्वालियर और चम्बल संभाग के सभी जिले के आवेदक सहायक कृषि यंत्री, ग्वालियर के नाम से बैंक ड्राफ्ट बनाएंगे। आवेदन पत्र 24 अप्रैल से 8 मई तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे। 9 मई 2023 को कम्प्युटराइज्ड लॉटरी से जिलेवार प्राथमिकता सूची का निर्धारण किया जाएगा। जिसे संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी के पोर्टल पर 9 मई को शाम 4 बजे देखा जा सकेगा। जिलेवार आवेदकों के अभिलेखों का सत्यापन एवं बैंक ड्राफ्ट जमा करने का समय 11-12 मई 2023 को सुबह 10:30 से शाम 5:30 तक किया जाएगा। एक से अधिक जिलों/ग्रामों के लिए आवेदन प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में आवेदक के सभी आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के सहायक कृषि यंत्री के कार्यालय से सम्पर्क करें।

276 पशु सखियों को मध्यप्रदेश और गुजरात में मिला ए-हेल्प प्रशिक्षण

पशुपालकों के आर्थिक उन्नति में मददगार बन रही हैं पशु सखी

भोपाल। जागत गांव हमार

पशुपालन मंत्री प्रेमसिंह पटेल ने बताया कि केन्द्रीय पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा मध्यप्रदेश से प्रारंभ पशु सखियों के प्रथम बैच की 276 पशु सखियों ने मध्यप्रदेश और गुजरात में ए-हेल्प का प्रशिक्षण पूरा कर लाभ उठाना आरंभ कर दिया है। प्रशिक्षण की शुरुआत 23 जुलाई-2022 में मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा चयनित पशु सखियों से हुई थी। इन्हें ए-हेल्प का आवासीय प्रशिक्षण राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद (गुजरात) और मध्यप्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के समन्वय से दिया गया, जो आगे भी जारी रहेगा। पशु सखियां पशुपालक और पशुपालन एवं डेयरी विभाग के बीच सेतु का कार्य कर रही हैं। ए-हेल्प मूलत: एनआरएलएम पंजीकृत महिला स्व-सहायता समूह की सदस्य हैं, जिन्हें पशुपालन गतिविधियों, योजनाओं, सामान्य घरेलू पशु उपचार, पशुओं की उचित देखभाल और संतुलित आहार से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया है। इससे ग्राम स्तर पर पशुपालकों को काफी लाभ मिलने के साथ महिला स्व-सहायता समूह भी आत्मनिर्भर बन रहे हैं।

पशुपालन गतिविधियों के विस्तार में होगी अहम भूमिका

प्रशिक्षण के बाद पशु सखियों को ए-हेल्प किट भी दिया गया है, जिसमें पशुपालन संबंधी पुस्तकें, एप्रेन, कैप, खाद्य सामग्री तौलने के लिये मशीन एवं अन्य जरूरी सामग्री है। पशुओं की संगणना, टेगिंग और पशुपालन गतिविधियों में विस्तार में भी ए-हेल्प की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ए-हेल्प पशु सखियों को पशुपालन से आमदनी बढ़ाने वाली योजनाओं से महिलाओं और ग्रामीणों को जोड़ने के लिए विशेष ट्रेनिंग दी गई है। प्रशिक्षण के बाद ए-हेल्प क्षेत्र में पशुओं की छोटी-मोटी बीमारियों का निस्तारण करने में समर्थ हुई हैं। दुधारु पशुओं के स्वस्थ रहने से दूध उत्पादन में बढ़ोत्तरी हो रही है। ए-हेल्प पशु सखी पशुपालकों की उद्यमिता विकास के लिये बैंक से लोन लेने, आवेदन भरने, पशुओं की टेगिंग और पशुधन बीमा आदि कार्यों में भी सहायता कर रही हैं।

251 कृषि अधिकारियों को दिए नियुक्ति पत्र, कहा- 15 अगस्त तक भरे जाएंगे एक लाख पद

मप्र के कृषि अधिकारी किसानों का भविष्य बनाने दें प्रामाणिक सेवाएं

भोपाल। जागत गांव हमार

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि क्षेत्र, अर्थ-व्यवस्था को मजबूत बनाने का कार्य करता है। मध्यप्रदेश ने कृषि के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। विभाग में पदस्थ किए गए वरिष्ठ कृषि विकास और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को किसानों का जीवन बदलने का जिम्मा मिला है। प्रदेश के किसानों का भाग्य बदलने और उनका भविष्य बनाने का महत्वपूर्ण दायित्व नव-नियुक्त कृषि अधिकारियों पर है। मध्यप्रदेश कृषि क्षेत्र में काफी आगे है। नव-नियुक्त कृषि अधिकारी परिश्रम और प्रामाणिकता से सेवाएं देते हुए यह संकल्प लें कि किसानों के जीवन को बदलने का माध्यम बनेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि विभाग के साथ अन्य विभागों में भी रिक्त पदों को भरने का अभियान चल रहा है।

आगामी 15 अगस्त तक विभिन्न विभागों में करीब एक लाख पदों की पूर्ति का कार्य पूरा हो जाएगा। नौजवानों को काम देकर मध्यप्रदेश को समृद्ध बनाएंगे। शिवराज ने मुख्यमंत्री निवास कार्यालय समत्व भवन में 251 वरिष्ठ कृषि विकास और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को नियुक्ति-पत्र प्रदान किए। इनमें 87 महिला अधिकारी शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नव-नियुक्त अधिकारियों की किसानों के लिए समर्पित भूमिका होगी तो वे जीवन सार्थक बना सकेंगे। मुख्यमंत्री ने नव-नियुक्त अधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कार्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण से हम किसानों की जिंदगी बदलने का कार्य कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने एक कहानी के माध्यम से एक कार्य करने वाले तीन श्रमिकों के तीन दृष्टिकोण का उल्लेख किया और कहा कि जो हमें दायित्व मिला है उसे सौभाग्य मान कर करें, इसी में सार्थकता है।

कृषि क्षेत्र में निरंतर आगे मध्यप्रदेश

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में 700 प्रतिशत अनाज उत्पादन बढ़ा है। देश की अर्थ-व्यवस्था में मध्यप्रदेश का योगदान बढ़ रहा है। प्रदेश की कृषि विकास दर बढ़ी है। आज मध्यप्रदेश भारत का फूड बास्केट कहलाने लगा है। देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 10वाँ हिस्सा सिर्फ मध्यप्रदेश उत्पन्न करता है। मध्यप्रदेश का सोयाबीन, दालें, मसाले और अदरक उत्पादन में देश में प्रथम गेहूं, मक्का और प्याज उत्पादन में द्वितीय, तिलहन और सुगंधित पौधों के उत्पादन में तृतीय स्थान है। प्रदेश में कृषि की नई तकनीक के उपयोग के साथ ही जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में कार्य की निरंतर अपार संभावनाएं होती हैं। खेती से अर्थ-व्यवस्था बदलती है। एक समय था जब भारत में अन्य देशों से गेहूं आता था। अब स्थिति भिन्न है। कृषि का तेजी से विकास हुआ। उत्पादन बढ़ा तो बाजार में खरीदी बढ़ी, कारखानों के पहिए चले तो संपूर्ण अर्थ-व्यवस्था को मदद मिली। प्रदेश में वर्ष 2012-13 में एक लाख करोड़ का बजट था, जो वर्ष 2020-21 में 2 लाख करोड़ से आगे बढ़ गया और वर्ष 2023 में 3 लाख 14 हजार करोड़ हो गया। प्रदेश में प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आय भी बढ़ी है। प्रदेश में प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आय कभी सिर्फ 11 हजार थी, जो अब बढ़ कर 1 लाख 40 हजार हो गई है।

मुख्यमंत्री ने प्रतीक स्वरूप कुछ अधिकारियों को नियुक्ति-पत्र प्रदान किए। उन्होंने नव-नियुक्त अधिकारियों के साथ समूह छायाचित्र भी खिंचवाए।

नियुक्ति के साथ मिली है खुशी

आज जिन 251 युवाओं को नियुक्ति मिली है उनमें खरगोन जिले के मुकेश बडोले, धार जिले के मिश्रीलाल वास्केल, सीहोर जिले की मधु मालवीय और अनिल कुमार अजनेरिया साधारण परिवारों से आते हैं। इन सभी ने बताया कि किसानों के कल्याण के लिए कार्य करने का अवसर मिलने पर उन्हें रोजगार के साधन के साथ ही हृदय से प्रसन्नता प्राप्त हुई है। पूरे परिश्रम से अपने दायित्व को निभाने के लिए संकल्पबद्ध हैं।

2805 पदों को भरने की प्रक्रिया जारी

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री निवास सभा कक्ष में आज 251 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को नियुक्ति-पत्र प्रदान किए। इनमें 241 पद ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और 10 पद वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी के हैं। इनमें 164 पुरुष और 87 महिलाएँ शामिल हैं। विभाग में नियमानुसार विभिन्न स्तर पर रिक्त पदों को भरने के लिए नियुक्तियां की जा रही हैं। कुल 2805 पदों को भरने के लिए प्रक्रिया जारी है। इनमें सर्वाधिक पद 1852 ग्रामीण विस्तार अधिकारियों के हैं। इसके अलावा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, प्रयोगशाला सहायक, स्टेनोग्राफर वर्ग तीन, स्टेनो टाइपिस्ट, ब्लाक टेक्नालॉजी मैनेजर, कम्प्यूटर आपरेटर, एकाउंटेंट और असिस्टेंट टेक्नालॉजी मैनेजर आदि के पद शामिल हैं।

अन्य टमाटर की अपेक्षा तीन गुना विटामिन सी

भोपाल का किसान कर रहा खास टमाटर की खेती

-भोपाल के किसान मिश्रीलाल राजपूत चैरी टमाटर-01 उगा रहे

-साधारण टमाटर से तीन गुना अधिक होता है विटामिन सी

भोपाल। जागत गांव हमार

चटक लाल रंग का गोल-मटोल टमाटर खट्टे स्वाद के लिए जाना जाता है, लेकिन यहां जिस टमाटर की बात हो रही है, उसका स्वाद मीठा है। इसके फल भी लंबी बेल में अंगूर के गुच्छों की तरह लगते हैं। साथ ही इसमें विटामिन सी की मात्रा भी आम टमाटर की तुलना में तीन गुना अधिक है। इस वजह से यह सर्दी-जुकाम और कोरोना जैसे संक्रमण से बचाने के लिए जरूरी विटामिन-सी का अच्छा विकल्प भी है। पहली बार इस चैरी टमाटर-वन की खेती राजधानी के खजूरीकलां में रहने वाले प्रगतिशील किसान मिश्रीलाल राजपूत ने शुरू की है। खजूरी कलां में अपने खेत में आधा एकड़ जमीन में मिश्रीलाल राजपूत ने चैरी टमाटर-वन की फसल लगाई है। हालांकि अभी उन्होंने प्रयोग के तौर पर टमाटर लगाया है, लेकिन शानदार उत्पादन देखकर वह काफी उत्साहित हैं। उन्होंने बताया कि विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (वीपीकेएएस) अल्मोड़ा के वैज्ञानिकों ने टमाटर की यह नई प्रजाति विकसित की है। इसका पौधा बेल की शक्ल में बढ़ता है। फल अंगूर से कुछ बड़े और गुच्छों में लगते हैं। अभी उन्होंने बीज तैयार करने के उद्देश्य से फसल

प्रचुर मात्रा में होता है विटामिन सी

विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ. लक्ष्मीकांत ने बताया कि वैज्ञानिकों ने लंबे परीक्षण के बाद वीएल चैरी टमाटर-1 नाम से टमाटर की नई प्रजाति विकसित की है। इसका खेतों में परीक्षण किया जा चुका है। इस प्रजाति को खास तौर पर उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, असम, अंडमान निकोबार और मध्यप्रदेश राज्य के लिए विकसित किया गया है।वीएल चैरी टमाटर-वन में विटामिन सी की मात्रा प्रति 100 ग्राम में 86 मिग्रा है, जबकि सामान्य टमाटर में यह मात्रा 32 मिलीग्राम होती है।

पैदावार भी अधिक होती है

वीपीकेएएस के विज्ञानी डॉ. निर्मल कुमार ने बताया कि टमाटर की यह प्रजाति खास तौर पर सलाद के लिए अधिक बेहतर मानी जा रही है। इस टमाटर का स्वाद मीठा होता है। इसके पेड़ की बेलें सामान्य टमाटर की अपेक्षा काफी बड़ी और फैली होती हैं, जिसकी पैदावार 350 से 375 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। फल अंगूर के गुच्छे की तरह लगते हैं और आम टमाटर की तुलना में इनका आकार छोटा होता है। इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होने के कारण यह टमाटर कोरोना संक्रमण से मुकाबले में भी काफी कारगर सिद्ध हो सकता है।

5 सदस्यीय जाँच कमेटी करेगी निरीक्षण

मत्स्य उत्पादन में कमी पर मंत्री ने व्यक्त की नाराजगी

भोपाल। जागत गांव हमार

जल संसाधन मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास मंत्री तुलसीराम सिलावट ने प्रदेश में मछली उत्पादन की समीक्षा की। उन्होंने पिछले 5 वर्षों में मछली उत्पादन में कमी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए 5 सदस्यीय जांच समिति बनाकर जांच करने के निर्देश दिए। समिति मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए आवश्यक सुझाव भी देगी। मंत्री ने मछुआ सहकारी समिति के कामकाज की समीक्षा की। बताया कि मुख्यमंत्री मीनाक्षी कन्या विवाह योजना में 5 साल में 677 कन्याओं को विवाह के लिए 20 हजार की अतिरिक्त राशि प्रदान की गई है। मंत्री सिलावट ने मछली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए नवाचार करने के निर्देश दिए। मछुआ क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए जिला के अधिकारी बैंक मैनेजर से चर्चा करे। मछुआ सहकारी समिति के सक्रिय सदस्य के कार्ड बनाए जाए। प्रमुख सचिव मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास कल्पना श्रीवास्तव ने भी मत्स्य उत्पादन की कमी पर प्रतिवेदन देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा की मछली के गुणवत्ता सुधार के लिए भीं कार्ययोजना बनाकर काम करे। प्रबंध संचालक पुरुषोत्तम दीवान, संचालक भरत सिंह और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

हर साल करीब 700 से 1000 भर्तियां करने की तैयारी

बाघों की रक्षा के लिए अग्निवीर की तर्ज पर जंगलवीर तैयार करेगी राज्य सरकार!

भोपाल। जागत गांव हमार

जंगल में रह रहे युवाओं रोजगार देने के लिए मप्र सरकार नई योजना पर काम कर रही है। सेना में अग्निवीर की तरह ही जंगल वीर मध्यप्रदेश में बाघों की रक्षा करेंगे। इसका प्रस्ताव मप्र सरकार के पास है, जिसे जल्द अंतिम रूप दिया जा सकता है। इसके मुताबिक मप्र के नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में या इसके आसपास रहने वाले लंबे-चौड़े 18 से 21 की उम्र के युवाओं का चयन कर उन्हें ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। इन्हें जंगल वीर नाम दिया जाएगा। इसके लिए वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड से अलग एक नया कैडर होगा।

मासिक वेतन 20 से 25 हजार रुपए - इस योजना के तहत हर साल करीब 700 से 1000 भर्तियां करने की तैयारी है। इन्हें फिक्स-पे के रूप में 20 से 25 हजार रुपए मासिक वेतन दिया जाएगा। पांच साल बाद इनमें से 25 से 50 फीसदी बाघ रक्षकों को स्थाई फॉरेस्ट गार्ड बनाया जा सकेगा। इसकी घोषणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हो सकती है। खास बात यह है कि इस भर्ती के लिए शारीरिक मापदंड और व्यवहारिक समझ को सर्वाधिक वेटेज दिया जाएगा। हालांकि न्यूनतम योग्यता 12वीं पास हो सकती है।

हमेशा बनी रहती है फॉरेस्ट गार्ड की कमी

गौरतलब है मप्र वन विभाग में वन रक्षकों के कुल 20670 पद हैं, लेकिन अभी 16875 वन रक्षक सेवाओं में हैं। 3795 पद खाली हैं। वन रक्षकों के लिए कर्मचारी चयन मंडल से परीक्षा ली जाती है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के युवा अक्सर पिछड़ जाते हैं और शहरी क्षेत्र के युवा बाजी मार लेते हैं। लेकिन बाद में दूसरी नौकरी मिलने पर वे वन रक्षक की नौकरी छोड़कर चले जाते हैं, इस कारण हमेशा फॉरेस्ट गार्ड की कमी बनी रहती है। प्रदेश में 8 बड़े नेशनल पार्क और दो बड़ी सेंचुरी हैं, जो टाइगर का स्थाई घर हैं। इनमें कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, सतपुड़ा, पन्ना और संजय डुबरी नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व हैं। जबकि माधव नेशनल पार्क, नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रातापानी सेंचुरी में टाइगर की अच्छी खासी तादाद है, तीनों को ही टाइगर रिजर्व बनाने के प्रस्ताव केंद्र व राज्य स्तर पर लंबित हैं।

जलवायु परिवर्तन का शिकार हो रहा कृषि और किसान

आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू (एएसआर) जिले के किसानों को 2020 और 2021 में लगातार दो सीजन में रागी और छोटे बाजरा (रागी) के बीज उत्पादन में नुकसान उठाना पड़ा। करीब 20 किसानों के समूह ने 2019 में आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती परियोजना के तहत रागी के बीज उत्पादन का काम शुरू किया था। संबंधित क्षेत्र में आदिवासी किसानों के साथ काम कर रहे वाटरशेड सपोर्ट सर्विसेज एंड एक्टिविटीज नेटवर्क (वासन) के कार्यक्रम प्रबंधक एमएल सन्यासी राव कहते हैं कि दोनों वर्षों में जुलाई और अगस्त के महीने में अधिक वर्षा ने फसलों की सेहत को प्रभावित किया। वह कहते हैं, यदि अनाज की गुणवत्ता जैसी सोची गई थी, वैसी नहीं है तो यह सीधे बीज की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। अधिक वर्षा ने पौधों को मिट्टी से पोषण नहीं लेने दिया।

जलवायु परिवर्तन के कारण वर्तमान में कई परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इससे बीजों के जीवित रहने की संभावना कम हो गई और अंकुरण (जर्मिनेशन) के विफल होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि निम्न गुणवत्ता वाले बीजों को अंकुरण के लिए लगाया जाए तो उन बीजों की गुणवत्ता ठीक नहीं होती है, जिसके परिणामस्वरूप बाद में फसल की उपज कम होती है। 2021 में किसानों को 20 टन (20,000 किलोग्राम) बीज की उम्मीद थी। लेकिन जब नवंबर में फसल काटी गई तो उन्हें केवल 15 टन उपज मिली और अनाज बीज उत्पादन और क्षेत्र के अन्य किसानों की आपूर्ति के लिए काम का नहीं पाया गया।

राव कहते हैं, अनाज कमजोर थे और उसमें एंडोस्पर्म गायब था। एंडोस्पर्म बीज का वह हिस्सा जो एक पौधे के विकास के लिए भोजन का भंडारण करता है और बीज के अंकुरण के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए बीज उत्पादन के लिए उसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। 20,000 किलो बीज को करीब 35 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा जाना था। हालांकि उसे 25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा गया। इससे किसानों को 3.25 लाख रुपए का सीधा नुकसान हुआ।

हरियाणा के करनाल जिले के एक किसान विकास चौधरी जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के बीज उत्पादन कार्यक्रम के अधीन भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) के साथ एक सहभागी किसान के तौर पर काम कर रहे हैं, कहते हैं, हल्के वजन या कमजोर अनाज की संख्या में पिछले साल लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आमतौर पर यह करीब 5-7 फीसदी होता है लेकिन पिछले साल यह 20-22 फीसदी था। इन अनाजों का उपयोग बीज उत्पादन के लिए नहीं किया जा सकता क्योंकि बाद में उपज कम होगी।

देश ने मार्च, 2022 में भीषण गर्मी की लहर देखी, जिसने गेहूं के दानों को झुलसा दिया था। इससे फसल की मात्रा और गुणवत्ता प्रभावित हुई थी और इसके परिणामस्वरूप उत्तर और मध्य भारतीय राज्यों में गेहूं की पैदावार कम हुई। भारत ने 2021-22 फसल सीजन में 106.84 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन किया जबकि 2021 में 109.59 मिलियन टन उत्पादन था।

गेहूं और धान देश में मुख्य खाद्यान्न हैं, जो सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीब आबादी को वितरित किए जाते हैं। ये हमारी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। वर्ष 2016 में एग्रीकल्चर जर्नल में प्रकाशित शोध जलवायु परिवर्तन-बीज उत्पादन और अनुकूलन के लिए विकल्प के मुताबिक, अधिकांश पौधे हल्के तापमान परिवर्तन को सहन कर सकते हैं। अधिक तापमान होने पर पहले यह बीज के अंकुरण प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाते हैं फिर इसका असर उपज पर पड़ता है। बीजों के परिपक्व होने से पहले ही यदि उच्च तापमान का तनाव उन तक पहुंचे तो यह अंकुरण को कम कर सकता है या फिर बीजों की

इस हद तक क्षति होती है कि वह अंकुरित होने की क्षमता खो देते हैं। इसके अलावा जर्मिनेशन के लिए जरूरी प्रक्रिया को भी बाधित कर सकता है।

चौधरी बताते हैं कि तापमान में वृद्धि से फसल के विकास में भी तेजी आती है, जिससे बीज भरने की अवधि कम हो जाती है। यह प्रजनन विकास और पराग निर्माण को भी गति देता है और छोटे बीजों के विकास की ओर ले जाता है। किसान बता रहे हैं कि वे गेहूं और धान के दानों में सिकुड़न देख रहे हैं। अगस्त, 2022 के दौरान धान में बौना वायरस पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड से रिपोर्ट किया गया था।

इस बीमारी के कारण स्टंटिंग और बौनापन हो गया और विशेषज्ञों ने कहा था कि मई और जून के महीनों के दौरान उच्च तापमान इसका एक कारण हो सकता है। अत्यधिक गर्मी फूलों के आने की प्रक्रिया को या तो जल्दी या देरी कर सकती है। सूखे और उच्च तापमान के प्रति चावल की बीज गुणवत्ता की संवेदनशीलता पर दिसंबर 2019 में सीड साइंस जर्नल में प्रकाशित शोध में कहा गया है कि चावल में बीज की गुणवत्ता को सबसे अधिक नुकसान तब होता है, जब संक्षिप्त गर्म मौसम शुरुआती बीज विकास के साथ मेल खाता है। और सूखा बीजों के शुरुआती विकास के दौरान परिपक्वता पर उनकी गुणवत्ता को भी कम कर देता है। जब ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं तो नुकसान और भी ज्यादा होता है।

धान के मामले में अधिक वर्षा से भी अनाज का रंग खराब हो जाता है। करनाल के किसान गुरनाल सिंह कहते हैं, 2022 में पहले बारिश कम हुई थी और धान के पौधों की जड़ें पहले से ही कमजोर थीं और फिर जब अचानक अधिक बारिश हुई तो पत्तियां क्लोरोफिल नहीं ले सकीं।

पिछले 15 साल से बीज उत्पादन से जुड़े किसान हरभगवान घई का कहना है कि कुछ सालों में लगातार और भारी बारिश से धान के पौधे में फूल आने की अवस्था पर असर पड़ रहा है। इससे धान की मजबूती व चमक प्रभावित होती है। फूल बनने की अवस्था में अधिक वर्षा होती है, तो यह परागण को प्रभावित करती है।

पराग न होने का सीधा मतलब है कि बीज नहीं बनना। इस साल भी तापमान में वृद्धि के अलावा किसानों के लिए एक और चिंता तेज हवाओं की रही है जो आमतौर पर मार्च के महीने में होने वाली घटना है। लेकिन इस बार फरवरी में भी तेज हवाएं चल रही हैं।

हरियाणा के सीधेपुर गांव के वीरेंद्र कुमार कहते हैं, यह वह समय है, जब गेहूं की फसल फूलों की अवस्था में होती है और परागण हो रहा होता है। अगर तेज हवा चले और किसान इस समय पानी दें तो पौधे की जड़ें हिलती हैं और अनाज मनचाहा नहीं उगता।

सेंट्रल यूरोपियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों की एक टीम ने कैनोला में बीज के विकास पर गर्म तापमान के प्रभाव का अध्ययन किया और पाया, बीज का एक हिस्सा फल के अंदर अंकुरित हो रहा है और बुवाई के अगले दौर के लिए संग्रहीत नहीं किया जा सकता है जबकि दूसरा भाग अव्यवहार्य भ्रूण पैदा करता है। बीज के भीतर पल रहा भ्रूण (मां के गर्भ में बच्चे की तरह) एक नए पौधे में अंकुरित होगा।

एक अव्यवहार्य भ्रूण विकसित नहीं होगा और इसलिए बीज की एक पूरी पीढ़ी नष्ट हो जाती है। विभिन्न शोध अध्ययनों से पता चला है कि विभिन्न फसलों में उच्च तापमान और अनाज की उपज पर प्रभाव के बीच संबंध के वैश्विक प्रमाण हैं।

मक्के में 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान से अनाज की सिंक क्षमता और उपज कम हो जाती है। जैसे ही औसत तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ता है, सोयाबीन में बीज वृद्धि दर और बीज का आकार 39 डिग्री सेल्सियस के औसत तापमान पर शून्य तक पहुंचने तक घट जाता है। सोयाबीन के बीज प्रोटीन सांद्रता को 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर दिखाया गया है। बीज भरने के चरण के दौरान गर्मी के तनाव की प्रतिक्रिया में तेल और प्रोटीन सांद्रता विपरीत रूप से संबंधित थे।

फसल के लिए लाभकारी ग्रीष्मकालीन की गहरी जुताई

» डॉ. बी एस किरार
» डॉ. आर.के. प्रजापति
» डॉ. एस के सिंह
» डॉ. सुनील कुमार जाटव
» डॉ. यू एस धाकड़
» डॉ. आई. डी. सिंह
» डॉ. जयपाल छिगारहा
वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र, टीकमगढ़

ग्रीष्मकालीन जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने पर खेत की मिट्टी ऊपर-नीचे हो जाती है। इस जुताई से जो ढेले पड़ते हैं वह धीरे-धीरे हवा व बरसात के पानी से टूटते रहते हैं साथ ही जुताई से मिट्टी की सतह पर पड़ी फसल अवशेष की पत्तियां, पौधों की जड़ें एवं खेत में उगे हुए खरपतवार आदि नीचे दब जाते हैं, जो सड़ने के बाद खेत की मिट्टी में जीवाश्म, कार्बनिक खादों की मात्रा में बढ़ोतरी करते हैं।

कृषि विज्ञान केंद्र, टीकमगढ़ के वरिष्ट वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को हल्की ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई कर फसल को रोग, कीट व्याधियों व खरपतवार से बचाने एवं जल संवर्धन बढ़ाने की सलाह डी गई। ग्रीष्मकालीन जुताई करने से खेत के खुलने से प्राकृतिक क्रियाएं भी सुचारू रूप से खेत की मिट्टी पर प्रभाव डालती हैं। वायु और सूर्य की किरणों का प्रकाश मिट्टी के खनिज पदार्थो को पौधों के भोजन बनाने में अधिक सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त खेत की मिट्टी के कणों की संरचना (बनावट) भी दानेदार हो जाती है। जिससे भूमि में वायु संचार एवं जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। इस गहरी जुताई से गर्मी में तेज धूप से खेत के नीचे की सतह पर पनप रहे कीड़े-मकोड़े बीमारियों के जीवाणु खरपतवार के बीज आदि मिट्टी के ऊपर आने से खत्म हो जाते हैं, साथ ही जिन स्थानों या खेतों में गेहूं व जौ एवं सब्जियों में निमेटोड पनापता है वहां पर इस रोग की गांठें जो मिट्टी के अन्दर होती हैं, जो जुताई करने से ऊपर आकर कड़ी धूप में मर जाती है।

ग्रीष्मकालीन जुताई के लाभ: 1. मिट्टी में कार्बनिक पदार्थो की बढ़ोतरी होती है। **2.** मिट्टी के पलट जाने से वायु एवं ऊष्मा का प्रभाव सुचारू रूप से मिट्टी में होने वाली प्रतिक्रियाओं पर पड़ता है और वायु तथा सूर्य के प्रकाश की सहायता से मिट्टी में विद्यमान खनिज अधिक सुगमता से पौधे के भोजन में परिणित हो जाते हैं। **3.** ग्रीष्मकालीन जुताई कीट एवं रोग नियंत्रण में सहायक है। हानिकारक कीड़े तथा रोगों के रोगकारक भूमि की सतह पर आ जाते हैं और तेज धूप से नष्ट हो जाते हैं। **4.** ग्रीष्मकालीन जुताई मिट्टी में जीवाणु की सक्रियता बढ़ाती है तथा यह दलहनी फसलों के लिए अधिक उपयोगी है। **5.** ग्रीष्मकालीन जुताई खरपतवार नियंत्रण में भी सहायक है। कांस, मोथा आदि के उखड़े हुए भागों को खेत से बाहर फेंक देते हैं। अन्य खरपतवार उखड़ कर सूख जाते हैं। खरपतवारों के बीज गर्मी व धूप से नष्ट हो जाते हैं। **6.** बारानी खेती वर्षा पर निर्भर करती है अत: बारानी परिस्थितियों में वर्षा के पानी का अधिकतम संचयन के लिए ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करना आवश्यक है। अनुसंधानों से सिद्ध हो चुका है कि ग्रीष्मकालीन जुताई करने से 31 प्रतिशत बरसात का पानी खेत में समा जाता है। **7.** ग्रीष्मकालीन जुताई करने से बरसात के पानी द्वारा खेत की मिट्टी के कटाव में कमी होती है अर्थात् अनुसंधान के परिणामों में यह पाया गया है कि गर्मी की जुताई करने से भूमि के कटाव में 66.5 प्रतिशत तक की कमी आती है। ग्रीष्मकालीन जुताई से गोबर की खाद व अन्य कार्बनिक पदार्थ भूमि में अच्छी तरह मिल जाने से पोषक तत्व शीघ्र फसलों को उपलब्ध हो जाते हैं।

ग्रीष्मकालीन जुताई के लिए मुख्य बातें: 1. ग्रीष्मकालीन जुताई हर दो-तीन वर्ष में एक बार जरूर करें। **2.** जुताई के बाद खेत के चारों ओर एक ऊँची मेड़ बनाने से वायु तथा जल द्वारा मिट्टी का क्षरण नहीं होता है तथा खेत वर्षा जल सोख लेता है। **3.**गर्मी की जुताई हमेशा मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी करनी चाहिए जिससे खेत की मिट्टी के बड़े-बड़े ढेले बन सकें, क्योंकि ये मिट्टी के ढेले अधिक पानी सोखकर पानी खेत के अन्दर नीचे उतरेगा जिससे भूमि की जलधारण क्षमता में सुधार होता है। **4.** खेतों की ग्रीष्मकालीन गर्मी की जुताई करेंगे तो निश्चित ही आपकी आने वाली खरीफ मौसम की फसलें न केवल कम पानी में हो सकेंगी, बल्कि बरसात कम होने पर भी फसल अच्छी हो सकेंगी तथा खेत से उपज भी अच्छी मिलेगी और लागत भी कम आयेगी।

'गंगा' से मिली राष्ट्रपति, कहा-किसानों की आय बढ़ाएगी यह तकनीक

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की पहली क्लोन गाय गंगा से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि यह तकनीकी न सिर्फ पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता में वृद्धि करेगी बल्कि किसानों की आय भी बढ़ाएगी। गिर नस्ल की इस क्लोन बछिया ने 16 मार्च, 2023 को जन्म लिया था। यह अब एक महीने 09 दिन की हो चुकी है। जन्म के वक्त गिर नस्ल की इस गाय का वजन 32 किलो था। देश की पहली क्लोन गाय गंगा के लिए उत्तराखंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड देहरादून और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने मिलकर काम किया। इन्होंने गिर, साहीवाल और रेड-सिंधी जैसी देशी गायों की क्लोनिंग का कार्य वर्ष 2021 में शुरू किया था। राष्ट्रपति ने 24 अप्रैल, 2023 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद - राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल के 19वें दीक्षांत समारोह में भी भाग लिया था। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा दुग्ध तथा दुग्ध के उत्पाद सदैव भारतीय भोजन तथा संस्कृति के अभिन्न अंग रहे हैं। भारत विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, लेकिन हमें दुग्ध के उत्पादों की बढ़ती मांग की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त, डेयरी सेक्टर भी अच्छी गुणवत्ता वाले चारे की उपलब्धता, जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम में बदलाव और पशुधन में रोगों जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। दुग्ध उत्पादन और डेयरी फार्मिंग को टिकाऊ बनाना हमारे सामने एक चुनौती है। पशु कल्याण को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण के अनुकूल और जलवायु स्मार्ट प्रौद्योगिकीयों को अपनाकर डेयरी उद्योग का विकास करना हम सभी का उत्तरदायित्व है। राष्ट्रपति ने कहा यह सेक्टर महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

देश की पहली क्लोन गाय गंगा: वैज्ञानिकों ने क्लोन बछिया तैयार करने के लिए तीन मवेशी नस्ल का इस्तेमाल किया। साहीवाल ब्रीड से ओऊसाइट यानी एक अंडाशय में एक कोशिका जो एक डिंब बनाने के लिए अर्धसूत्री विभाजन से गुजर सकती है उसे लिया गया। वहीं सोमेटिक कोशिका गिर ब्रीड से ली गई और एक क्रॉसब्रीड का सरोगेट एनिमल लिया गया। प्रजनन क्लोनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक मौजूदा जीव की एक सटीक अनुवांशिक प्रतिकृति, या क्लोन, एक प्रकार के क्लोनिंग के माध्यम से बनाई जाती है जिसे सोमैटिक सेल परमाणु हस्तांतरण कहा जाता है। इसमें अंडे की कोशिका के केंद्रक को हटाना और क्लोन किए जाने वाले जीव से एक दैहिक कोशिका के केंद्रक को प्रतिस्थापित करना शामिल है।

बड़वानी जिले में 50 गांवों के नाम औषधीय वनस्पतियों पर आधारित

विलुप्ति की कगार पर नीम से पहचाने जाने वाले निमाड़ के कई गांवों में औषधीय पौधे

बड़वानी। जागत गांव हमार

नीम की आड़ यानी निमाड़... से पहचाने जाने वाले निमाड़ के चारों जिलों में 100 से अधिक छोटे-बड़े गांव-फलियों के नाम औषधीय वनस्पतियों पर आधारित हैं। अकेले बड़वानी जिले में ही 50 गांवों के नाम जंगल की बेशकीमती और स्वास्थ्यवर्धक औषधियों के नाम पर पड़े हैं। अब समय के साथ ये औषधियां विलुप्त हो गई हैं और रह गए हैं तो सिर्फ यादें, इनके नाम। इन गांवों में पाई जाने वाली औषधियों पर अग्रणी महाविद्यालय की वनस्पति विभाग की टीम विशेष रूप से रिसर्च(शोध) कर रही है। विभागाध्यक्ष एवं पर्यावरणविद् डॉ. वीणा सत्य के निर्देशन में विद्यार्थियों की टीम ने इस पर रिसर्च कर पता लगाया कि कौन से गांव वनस्पतियों पर आधारित हैं।

डॉ. वीणा सत्य के अनुसार प्रकृति से मानव समाज का गहरा संबंध है। जीवन के हर पहलू में, दैनिक उपयोग में, सामाजिक रीति-रिवाजों में, धार्मिक संस्कारों में, मनुष्य ने पेड़-पौधों, जीव-जंतुओं को शामिल किया है। निमाड़ क्षेत्र का नाम भी नीम के पेड़ों की बहुतायत के कारण रखा गया है। बड़वानी जिले के लगभग 50 गांवों के नाम 25 पौधों के आधार पर रखे गए हैं। नामकरण का आधार उस क्षेत्र के जंगलों में बहुतायत से पाए जाने वाले वृक्ष, झाड़ियां और अन्य वनस्पतियां होती हैं। मूल शब्द पौधों का नाम रहता है, उसके साथ पानी, झिरी, पड़ावा, खेडी, कुंड, गांव, डेब आदि शब्द जोड़ दिए जाते हैं। ये पौधे खाने योग्य फल, सब्जी, चारा, काष्ठ, गोंद, औषधि इत्यादि प्रदान करते हैं। इनका सामाजिक और धार्मिक महत्व भी है। इस पर धुले, जलगांव, नासिक आदि जिलों के वनस्पति के प्राध्यापकों ने शोध कार्य किया है और शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। नामकरण की इस विधा को टोपोनिमी कहा जाता है।

कुछ महत्वपूर्ण वृक्षों के आधार पर गांवों के नाम

गांव	औषधियों के नाम की सारणी
धमनई, धामन्या	धामन (औषधि)
पिपरी, पिपराणी, पीपरकुंड पीपरी	काष्ठ, औषधीय वृक्ष
कुसम्याकुसुम	काष्ठ, औषधीय वृक्ष
बेहड़िया	बहेड़ा (खाने योग्य फल, औषधीय वृक्ष)
रोसर	रोशा घास (तेल, औषधीय पौधा)
धावड़ी, धवली, धावड़ा	(गोंद, औषधीय वृक्ष)
शिवनीपडवा, शिवनी	सीवन (काष्ठ, औषधीय)
आंवली	चमार आंवली (चर्म उद्योग)
कुंभीखेत	कुंभी (काष्ठ, औषधीय)
सिंधी, सिंदी	सिंडोला (खाने योग्य फल, औषधीय)
अंजनगांव	अंजन (काष्ठ, चारा)
बीजापुरी	बीजासाल (काष्ठ, औषधि)
अभाली	अभई (सब्जी)
हिंगवा	हिंगोट (एक प्रकार के पटाखे निर्माण)
उमरदा	उंबर, गूलर (खाने योग्य फल, औषधि)
अंजराड	अंजीर (खाने योग्य फल, औषधि)

केला के आधार पर केली केलपानी नाम रखे गए

आम के वृक्ष के आधार पर अंबापानी, आमल्यापानी, आमडा, आमझिरी, आभीझिरी, अंबावतार, बेर के वृक्ष के आधार पर बोरी, बोरलाय, बोरखेड़ी, बोरली, जामुन वृक्ष के आधार पर जामन्या, जाम वृक्ष के आधार पर जामती, जामपाती, पलाश वृक्ष के आधार पर पलासपानी, पलासिया, बेल वृक्ष के आधार पर बिलवा डेब, बिलवा रोड, पीपल के आधार पर पिपल्या, पिपलाज, पीपलधर, पिपल्याडेब, केला के आधार पर केली, केलपानी नाम रखे गए हैं।

अन्य प्रदेशों में भी गांवों के नाम वनस्पतियों पर आधारित

मध्य प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बंगाल, गुजरात में भी गांवों के नाम वहां की स्थानीय वनस्पति के आधार पर रखे गए हैं, लेकिन विकास की अंधाधुंध दौड़ में कई पेड़-पौधे विलुप्ति की कगार पर हैं। जिन पेड़-पौधों ने जिले के स्थानीय क्षेत्रों और गांवों को अपना नाम, अपनी पहचान दी है, वे स्वयं अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अत: पौधारोपण कार्यक्रमों के दौरान इन स्थानीय वनस्पतियों को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए, जिससे इन गांवों-स्थानों की पहचान स्थानीय जैव विविधता का संरक्षण किया जा सके।

एफपीओ, सब्जी एवं दुग्ध उत्पादक संगठनों के कार्यालयों का किया शुभारंभ

एफपीओ से प्रदेश के किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग होगा प्रशस्तः कृषि मंत्री

भोपाल। जागत गांव हमार

किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने सतना जिले के मैहर में मैहर कृषक उत्पादक संगठन एवं मझगवां के ग्राम पगारकलां में गैवीनाथ सब्जी एवं दुग्ध उत्पादक संगठन के कार्यालयों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार एफपीओ से कृषकों के आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त कर रही है। सांसद गणेश सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष रामखेलावन कोल, जन-प्रतिनिधि और ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

कृषि मंत्री ने कहा कि कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) द्वारा संबद्ध कृषकों को कृषि के लिये बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। एफपीओ कृषकों को बेहतर, गुणवत्तापूर्ण बीज, खाद, दवाई इत्यादि की व्यवस्था करने के साथ उपज की मॉर्केटिंग की व्यवस्था भी करते हैं। प्रदेश में निरंतर एफपीओ का गठन किया जा रहा है। मैहर में गठित एफपीओ निश्चित ही किसानों के लिये फायदेमंद होगा।

कृषि मंत्री ने मझगवां में गैवीनाथ सब्जी एवं दुग्ध उत्पादक संगठन कार्यालय का शुभारंभ करते हुए कहा कि समूह के गठन से किसानों को मदद मिलेगी। किसानों को सब्जी एवं दूध की तकनीकी जानकारी मिलने से

उत्पादन बढ़ेगा। क्षेत्र में पैक्ड दूध, क्रीम, मक्खन, दही, पनीर, कस्टर्ड, फ्रोजन सब्जियों के संबंध में नवीनतम जानकारियां मिलेंगी, जिससे किसान अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकेंगे।

किसानों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से अवगत कराया

कृषि मंत्री ने किसानों के हित में केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से गांव में रहने वाले लोगों को उनके मकान का मालिकाना हक प्रदान किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान-कल्याण योजना से किसानों को सीधे लाभान्वित किया जा रहा है। किसानों को खाद एवं बिजली बिलों में बड़े स्तर पर सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है।

पशुओं में मुंहपका-खुरपका टीकाकरण के दूसरे चरण में भी मध्यप्रदेश देश में आगे

भोपाल। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री प्रेमसिंह पटेल ने कहा है कि पशुओं में मुंहपका और खुरपका (फूट माउथ डिसीज) टीकाकरण के द्वितीय चरण में भी मध्यप्रदेश देश में सर्वप्रथम है। प्रदेश ने निर्धारित अवधि से पूर्व 15 फरवरी 2023 को 2 करोड़ 7 लाख 68 हजार गौ-भैंस वंशीय पशुओं का टीकाकरण पूर्ण कर लिया, जो देश में सर्वाधिक है।

एफएमडी रोग पशुधन उत्पादों को सर्वाधिक आर्थिक हानि पहुंचाने वाला रोग - मंत्री पटेल ने बताया कि राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम में होने वाले एफएमडी टीकाकरण के प्रथम चरण में प्रदेश में 2 करोड़ 52 लाख गौ-भैंस वंशीय पशुओं का टीकाकरण किया गया था। इसमें भी मध्यप्रदेश सबसे आगे था। एफएमडी रोग पशुधन उत्पादों को सर्वाधिक आर्थिक हानि पहुंचाने वाला रोग है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनीमल हेल्थ की प्राथमिकता में शामिल इस रोग के उन्मूलन का लक्ष्य वर्ष 2030 है।

मुंहपका एवं खुरपका बीमारी से पशुओं को बचाने का सबसे बेहतर उपाय टीकाकरण

मुंहपका एवं खुरपका बीमारी से पशुओं को बचाने का सबसे बेहतर उपाय टीकाकरण ही है। बछिया-बछड़े को पहला टीका 4 माह की उम्र में और दूसरा बूस्टर टीका एक माह बाद लगवाना चाहिये। इस बीमारी में पशु को जाड़ा देकर तेज बुखार आता है और भूख कम हो जाती है। मुंह से लार बहने लगती है। मुंह और खुर पर छोटे-छोटे छाले बन जाते हैं, जो बाद में बड़ा छाला बनने के बाद जख्म में बदल जाते हैं। दुधारु पशुओं का दूध उत्पादन 80 प्रतिशत तक घट जाता है। पशु कमजोर होने लगते हैं। प्रभावित पशु स्वस्थ होने के बाद भी लम्बे अरसे तक कमजोर ही रहते हैं। पशु के बीमार होने पर तुरंत पशु चिकित्सक की सलाह लें और प्रभावित पशु को अलग रखने के साथ पशु-शाला को साफ-सुथरा और संक्रमणनाशी दवाओं का छिड़काव करवाते रहें। एफएमडी रोग का उन्मूलन पशु-पालकों को आर्थिक रूप से काफी मजबूत बनाएगा।

प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ कर 45 लाख हेक्टेयर हुआ

मत्स्य उत्पादन में बालाघाट जिला देश में प्रथम स्थान पर

भोपाल। जागत गांव हमार

प्रदेश में पहले सिंचाई का रकबा 7 लाख हेक्टेयर हुआ करता था, जो अब बढ़ कर 45 लाख हेक्टेयर हो गया है प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक प्रदेश का सिंचाई रकबा 65 लाख हेक्टेयर कर दिया जाए इसके लिए नवीन सिंचाई परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। जल संसाधन एवं मछुआ कल्याण मंत्री तुलसीराम सिलावट नीमच जिले के रामपुरा में शनिवार को मछुआ कॉलोनी में बनने वाले सामुदायिक भवन का शिलान्यास कर मछुआ बंधुओं से संवाद कर रहे थे। सांसद सुधीर गुप्ता, मनासा विधायक अनिरुद्ध मारू, विधायक गरोठ देवी लाल धाकड़ सहित जन-प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

मंत्री सिलावट ने कहा कि मत्स्य उत्पादन में बालाघाट जिला देश में प्रथम स्थान पर है। गांधी सागर जलाशय में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मांग और गुणवत्तापूर्ण कतला, रऊ, प्रजाति मत्स्य का बीज भी डाला जाएगा। उन्होंने कहा कि मछुआरों को नाव के लिए प्रदान किए जा रहे 12 हजार रुपए को बढ़ा कर 15 हजार रुपए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मछुआरों की मछली पकड़ने की मजदूरी बढ़ाने की मांग के प्रस्ताव को मत्स्य महासंघ की बैठक में रखा जाएगा उन्होंने मछुआरों की विभिन्न मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने की बात भी कही। मंत्री ने कहा कि मत्स्य महासंघ गांधी सागर रामपुरा के अनियमितता करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

मंत्री ने गांधी सागर से मनासा क्षेत्र एवं नीमच जिले की सिंचाई योजना में छुटे हुए मनासा क्षेत्र की 10 ग्राम पंचायतों को शामिल करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसके लिए सर्वे का कार्य भी शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा और छूटे हुए गांव को भी गांधी सागर से सिंचाई की योजना में शामिल किया जाएगा। मंत्री सिलावट ने सांसद एवं विधायक के साथ रामपुरा में मत्स्य महासंघ के फिश कलेक्शन सेंटर का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए।

अनाज को सुरक्षित सुरक्षित भंडारण कर नुकसान से बचाएं

वैज्ञानिकों ने बताया सुरक्षित भंडारण कर अनाज को नुकसान से कैसे बचाएं

टीकमगढ़। जागत गांव हमार

कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. बीएस किरार साथ ही केंद्र के वैज्ञानिक डॉ. आरके प्रजापति, डॉ. एसके सिंह, डॉ. यूएस धाकड़, डॉ. एसके जाटव डॉ. आईडी सिंह एवं जयपाल छिगारहा द्वारा किसानों को अनाज को भंडारण सुरक्षित रखने की तकनीक सलाह समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित की जा रही है। किसान अनाज उगाने में काफी मेहनत एवं राशि खर्च करता है, लेकिन अनाज को सही तरीके से भंडारण नहीं कर पाता है। जिससे गोदाम एवं घरों में रखे अनाज एवं दलहन उत्पादन में काफी मात्रा कीट व्याधियों से या नमी से खराब हो जाता है, जिससे किसानों की आय में काफी नुकसान होता है। किसान तकनीकी जानकारी एवं आधुनिक भंडारण पत्रों में अनाज को रखने से कीड़े, चूहे एवं नमी से होने वाली आर्थिक क्षति को रोक सकते हैं।

सुरक्षित अनाज भंडारण के सिद्धांत-अनाज को भंडार से पूर्ण अच्छी तरह सुखा लें जिसमें नमी की मात्रा 10 प्रतिशत से अधिक न हो। अनाज से भरे बौरों को लकड़ी की पट्टियों पर रखें जिससे नमी अथवा सीडन से बोरे प्रभावित न होने पाए जहां तक संभव हो सके धातु भंडारण पात्रों का ही प्रयोग करें कीड़ों से नुकसान को समाप्त करने के लिए धूम्र एल्युमीनियम फास्फाइड या जिंक फास्फाइड दवा मिलाकर रख दें। दालों पर सरसों के तेल का लेप करके भंडारण करने पर भी धुन से बचाया जा सकता है। जिस भंडारण पात्र में अनाज भण्डारण करना हो उसके नीचे व ऊपर नीम की पत्तियां विछा दें। भंडारित अनाज के नुकसान में कीड़ों के साथ चूहों द्वारा नुकसान होता है। चूहे न केवल भंडारित अनाज को खाते ही नहीं, अपुति बर्बाद भी करते हैं एक चूहा अपने मलमूत्र से खाने के 10 गुना तक अनाज नष्ट करते हैं।

चूहा रोकथाम के उपाय

भण्डारण पात्रों को चूहों को चूहेदानी की सहायता से पकड़कर। जहरीले चारे जैसे जिंक फास्फाइड का उपयोग कर चूहों का नियंत्रण कर सकते है

कीट वर्ग- भंडारण में विभिन्न कीट भी अनाज को क्षति पहुंचाते हैं। अनाज के शत्रु हमारे कुल उत्पादन का लगभग 9-10 प्रतिशत प्रति वर्ष नष्ट कर देते है भण्डार ग्रह की अनुकूलता व परिस्थितियां इन कीटों की संख्या व प्रकोप को प्रभावित करती है ।

भण्डारित अनाज में नमी की मात्रा सुरक्षित भंडारण के लिए अनाज में अधिकतम 10 प्रतिशत या इससे कम नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर बीजावरण में कठोरता बनी रहती है जिससे कीट व अन्य सूक्ष्म जीवाणु अपने में सफल नहीं हो पाते है ।

खपरा बीटल (भृंग)- यह गेहूं के साथ-साथ सभी अनाज, दलहनों व तिलहनो को नुकसान पहुंचाता है। इसकी इल्ली दाने के अन्दर व सतह दोनों को नुकसान पहुंचाती है।

अनाज छेदक- इसकी इल्ली तथा वयस्क अनाज को नष्ट कर चूर्ण (दुर्गन्धयुक्त) बना देते है।

अनाज का घुन- यह अनाज के साथ अनाज उत्पादों दोनों को खाता है जबकि इल्ली दानों को खोखला कर देती है।

टारा भृंग- इसकी इल्ली व वयस्क दोनों ही गेहूं, मक्का, ज्वार, मैदा, सूजी को क्षति पहुंचाते है।

अनाज का पंतगा- इसकी इल्ली अनाज को खराब कर देती है तथा इसकी विशेषता है कि नुकसान पहुंचाए अनाज के गुच्छे बन जाते है

दाल की बीटल (भृंग)- यह दलहनों को नुकसान पहुंचाती है। यह खेत से ही क्रियाशील हो जाती गोदाम का पंतगा यह खेत में ही सक्रिय हो जाता है। भंडारण ग्रह में इसकी इल्ली दानों को खाकर अन्दर ही अन्दर खोखला कर देती है।

कीट वर्ग के रोकथाम से उपाय- भण्डारण के अच्छे उपायों का पालन करने के साथ-साथ भण्डारण के पूर्व भण्डार गृह, पात्रों तथा बोरों पर मैलाथियान 50 ईसी पोल का 1: बनाकर छिड़काव करें।

नियंत्रण- प्राय: धुम्र कीटनाशक जैसे ईडीवी एल्यूमीनियम फॉस्फाइड का प्रयोग कीट नियंत्रण में किया जाता है। इसका उपयोग 3 मि.ली. प्रति 100 किलो अनाज पर प्रभावी होता है। एल्यूमीनियम फॉस्फाइड की 2 ग्राम की 1-2 गोली एक टन अनाज के प्रधुमन के लिए प्रभावी होती है।

आष्टा मंडी में में टूटा 60 साल का रिकॉर्ड

अब तक सबसे ज्यादा 39 लाख क्विंटल की आवक 18 करोड़ रुपए की आय

सीहोर। जागत गांव हमार

जिले की एक कृषि उपज मंडी ने साठ सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये रिकॉर्ड आवक और आय को लेकर था। इस बीते वित्तीय वर्ष में 39 लाख क्विंटल से ज्यादा की आवक हुई है, वहीं 18 करोड़ से अधिक की आय मिली है। मंडी समिति आष्टा ने अपने स्थापना के वर्ष 1962 से आज दिनांक तक आवक एवं आय में रिकार्ड वृद्धि करते हुए लक्ष्य की प्राप्ति की है।

जानकारी के मुताबिक सीहोर जिले में आने वाली आष्टा कृषि उपज मंडी ने ये कमाल किया है। मंडी समिति के भारसाधक अधिकारी एसडीएम आनंद सिंह राजावत, मंडी सचिव राजेश साकेत एवं व्यापारी संघ अध्यक्ष रूपेश राठौर ने किसानों को असुविधा न हो, इस पर भी विशेष ध्यान दिया। उसी का परिणाम है कि न केवल आष्टा विकासखंड अपितु आसपास के अन्य जिलों की तहसीलों से भी यहां पर उपज बिकने के लिए आती रही। बीते साल कृषि उपजों की आवक 39 लाख 26 हजार 880 क्विंटल दर्ज की गई है। मंडी राजस्व की राशि भी पिछले वर्षों की अपेक्षा में वित्तीय वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक मंडी राजस्व राशि 18 करोड़ 13 लाख 19 हजार 732 रुपए प्राप्त की गई है। जो कि गत 60 वर्षों का एतिहासिक रिकॉर्ड है। पिछले वर्ष 1 अप्रैल 22 से 24 अप्रैल 22 तक मंडी की कुल आवक 4 लाख 97 हजार 487 क्विंटल थी, जिसकी तुलना में इस वर्ष 1 अप्रैल 23 से दिनांक 24 अप्रैल 23 तक आवक 8 लाख 64 हजार 211 क्विंटल मंडी में दर्ज की गई है, जो कि निरंतर ओर बढ़ती जा रही है।

60 वर्षों का ऐतिहासिक रिकॉर्ड

मंडी सचिव राजेश कुमार साकेत ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में मंडी समिति आष्टा में मंडी की स्थापना वर्ष 1962 से वित्तीय वर्ष 2022-23 तक कि स्थिति में वर्ष 2022-23 में सबसे अधिक मात्रा में कृषि उपजों की आवक 39 लाख 26 हजार 880 क्विंटल दर्ज की गई है। साथ ही मंडी राजस्व की राशि भी पिछले वर्षों की अपेक्षा में वित्तीय वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक मंडी राजस्व राशि 18 करोड़ 13 लाख 19 हजार 732 रुपए प्राप्त की गई है। जो कि गत 60 वर्षों का ऐतिहासिक रिकॉर्ड है।

उद्यानिकी के कमिश्नर ने देखी बालाघाट में बैगा आदिवासियों की हाइटेक करेला की खेती

भोपाल। भारत सरकार के उद्यानिकी कमिश्नर डॉ. प्रभात कुमार ने बालाघाट जिले के जनजातीय क्षेत्रों में बैगाओं द्वारा की जा रही हाइटेक करेला खेती का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद कमिश्नर डॉ. प्रभात कुमार ने इसकी प्रशंसा की। कमिश्नर ने जनजातीय बाहुल बिरसा विकासखंड के ग्राम बासिनखार बैगा टोला पहुंच कर करेला खेती को देखा। वे खेती से प्रभावित हुए। उन्होंने ग्रामीणों को अन्य सब्जियों की पैदावार लेने की सलाह दी। कमिश्नर ने बताया कि बालाघाट जिले में काजू उत्पादन की काफी अच्छी संभावनाएं हैं। इसका लाभ जनजातीय किसानों को लेना चाहिए। उन्होंने खाली पड़ी जमीन पर काजू के पौधे लगाने की सलाह दी।

बिरसा में काजू प्लांटेशन का निरीक्षण किया

उन्होंने ग्राम गोवारी भिमलाट और ग्राम बिरसा में काजू प्लांटेशन का निरीक्षण भी किया। दौरे के समय कमिश्नर के साथ राष्ट्रीय काजू बोर्ड के एडिशनल कमिश्नर डॉ. नवीन कुमार पटले भी मौजूद थे। उन्होंने कृषि विज्ञान केन्द्र बड़गांव के प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. आरएल.राउत और कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों से उद्यानिकी खेती के विस्तार के संबंध में चर्चा की।

सतपुड़ा अंचल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से सहायता समूहों की 2075 महिलाएं जुड़ीं

मोटे अनाज से बने उत्पाद मार्केट में उतारने की तैयारी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार देने के प्रयास

सतीष साहू। बैतूल

जिले के शाहपुर क्षेत्र में कार्यरत सतपुड़ा अंचल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी शीघ्र ही मोटे अनाज कोदो-कुटकी एवं सांवा से तैयार रवा, इडली मिक्स, खिचड़ी, बिस्किट, मल्टीग्रेन आटा, चिक्की एवं पापड़ जैसे उत्पाद बाजार में उतारेगी। इन उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार देने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। मोबाइल एप पर भी यह उत्पाद उपलब्ध कराए जाएंगे। गत दिनों एफपीओ के प्रतिनिधियों द्वारा कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस को उक्त उत्पाद भेंट किए गए। नाबार्ड के वित्तीय सहयोग से उक्त एफपीओ द्वारा इन उत्पादों को बाजार में उतारने की पहल की गई है। एफपीओ से शाहपुर क्षेत्र की एनआरएलएम के स्व सहायता समूहों की 2075 महिलाएं जुड़ी हैं। विगत खरीफ सीजन में साढ़े तीन सौ महिलाओं को कोदो-कुटकी एवं सांवा का बीज प्रदान किया गया। इस बीज को सामान्यत: अनुपयोगी कृषि भूमि में उपयोग किया गया। इससे बेहतर परिणाम प्राप्त हुए एवं लगभग 40 टन मोटे अनाज का उत्पादन हुआ।

इन महिलाओं को अनाज के बदले एफपीओ द्वारा 12 लाख रुपए का भुगतान किया गया। जिससे प्रति महिला को लगभग 12 हजार रुपए तक की आय हुई।

एफपीओ से जुड़ी 2075 महिलाओं को एफपीओ के शेयर्स से जोड़ा गया है। प्रतिवर्ष होने वाला आर्थिक लाभांश शेयर से जुड़ी हर महिला को मिलेगा। एफपीओ के मोटे अनाज से उत्पादित सामग्री की बेहतर मार्केटिंग के लिए नीर हार्टिकल्चर कंपनी गुजरात से अनुबंध किया जा रहा है। एफपीओ द्वारा विगत 18-19 मार्च को दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ मिलेट्स में भी अपने उत्पादों का स्टॉल लगाया गया। इस दौरान 25 देशों के प्रतिनिधियों से भी मिलेट्स एवं मिलेट्स उत्पाद विक्रय के संबंध में चर्चा हुई। आदिवासी महिलाओं के उत्पादों को पहचान देने के लिए उक्त उत्पाद ट्रायबल वूमंस फार्मर कंपनी के नाम से तैयार किए जा रहे हैं। एफपीओ की पांचों संचालक महिलाएं ही हैं।

खेत में पहुंचे केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री गिरिराज किसानों से की चर्चा

रीवा। रीवा जिले में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रीवा आए केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री गिरिराज किशोर सिंह ने रीवा जिले में कृषि विज्ञान केन्द्र व उद्यानिकी विभाग द्वारा किसानों के खेतों में प्रदर्षित नवाचारों का अवलोकन व भ्रमण किया। गिरिराज किशोर सिंह ने उक्त अवसर पर ग्राम रीठी एवं सिरखिनी में नवीन तकनीकी के नवाचार-पाली हाउस, गुलाब व शिमला मिर्च की खेती, टमाटर व धनिया के खेती के अंतर्गत कृषकों के प्रक्षेत्रों का भ्रमण किया एवं किसानों से चर्चा की। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केन्द्र के उद्यान वैज्ञानिक डा. राजेश सिंह ने कृषि आय दुगुनी करने के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र के द्वारा प्रदर्षित नवाचारों से मंत्री को अवगत कराया। गिरिराज किशोर सिंह ने उक्त कार्यों की सराहना करते हुए कृषि विज्ञान केन्द्र की उपयोगिता पर चर्चा की। उक्त अवसर पर सहायक संचालक उद्यानिकी एवं कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केन्द्र के अधिकारी व वैज्ञानिक उपस्थित रहे।

वैज्ञानिकों ने दी फसलों को लू से बचाव की सलाह

टीकमगढ़। इस समय मौसम के तापमान में लगातार परिवर्तन हो रहा है। तापमान 42 डिग्री सेल्सियस उपर हो रहा है, तो कभी-कभी बारिश एवं हवा के कारण तापमान नीचे गिर जा रहा है। यह परिवर्तन फसलों के लिए नुकसानदायक है। फसलों में अधिक तापमान के कारण उपर से पत्तियों का जलते हुए नीचे आना प्रमुख लक्षण है। साथ ही कीट बीमारियों का प्रकोप भी बढता है। जिसके कारण पौधों बढ़वार प्रभावित होती है। फसलों को हीटस्ट्रोक से बचाने के लिए सिचाई के समुचित व्यवस्था रखें एवं कीट बीमारियों के नियत्रंण के लिए आर्गेनिक बायोपेस्टी साइड एवं प्राकृतिक घटकों का प्रयोग करें। आर्गेनिक बायोपेस्टी साइड अंतर्गत कीट नियंत्रण (इल्ली/दीमक) के लिए बबेरिया बेसियाना, मेटाराइजियम ऐनासोपली 1ली./हेक्ट./500 लीटर पानी, चूसक कीट नियंत्रण हेतु बर्टिसीलियम लेकेनी 1ली/हेक्ट. का प्रयोग करें। प्राकृतिक घटकों में पौध बढ़वार के लिए जीवामृत/घनजीवामृत एवं कीट नियंत्रण के लिए नीमास्त्र, ब्रहास्त्र, सप्तदर्शी फफूंद नियंत्रण के लिए प्राकृतिक घटक में दशपर्णी एवं जैविक नियत्रंण टाइकोडर्मा, स्यूडोमोनोस का प्रयोग करें। उपरोक्त जैविक एवं प्राकृतिक घटाकों का प्रयोग करने से फसल सुरक्षित तो होगी। साथ ही गुणवत्तायुक्त उत्पाद प्राप्त होगा। विस्तृत जानकारी के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र के पादप संरक्षण वैज्ञानिक डॉ. एसआर शर्मा, कृषि विज्ञान केन्द्र नरसिंहपुर से स्वंय मिलकर/ दूरभाष/ व्हाट्सअप पर रोगी पौधों का फोटो मो. न. पर समस्या उन्मूलन के लिए सलाह प्राप्त कर सकतें।

कृषि वैज्ञानिकों ने किया ड्रोन द्वारा कीटनाशक छिड़काव का प्रदर्शन

हरदा। कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों ने सब्जी फसलों टिंडा, ककड़ी, मिर्च, मूंग में ड्रोन द्वारा कीटनाशक के छिड़काव का प्रत्यक्ष प्रदर्शन किया। 221 किसानों ने इस तकनीक को देखा। कृषि विज्ञान केन्द्र प्रमुख डॉ. संध्या मूरे ने बताया कि हरदा कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों ने जिले के ग्रामों हंडिया, कचबेड़ी, सोनतालाब मे किसानों को ड्रोन से कीटनाशक के छिड़काव दिखाया। लगभग 221 किसानों ने इस तकनीक को उत्साह के साथ प्रत्यक्ष देखा। इस दौरान किसान इस तकनीक के प्रति अति उत्साहित दिखे, उन्होने बताया कि यह तकनीक कृषि क्षेत्र में नवीन क्रांति लाएगी, क्योंकि इससे सीजन में श्रमिकों की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। शीघ्र ही यह तकनीक कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से जिले में फैलेगी।

40 से 60 प्रतिशत तक मिलता है सरकारी अनुदान

किसानों की अतिरिक्त आय का जरिया बन सकता है बकरी पालन

भोपाल। जागत गांव हमार

बड़े पशुओं की तुलना में बकरी पालन पशुपालकों के लिए आर्थिक रूप से काफी फायदेमंद है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा बैंक ऋण एवं अनुदान पर बकरी इकाई योजना संचालित है। इसमें हितग्राही को 10 बकरी और एक बकरा दिया जाता है। इकाई की लागत 77 हजार 456 रुपए है। सामान्य वर्ग के हितग्राही को इकाई लागत का 40 प्रतिशत और अनुसूचित जाति-जनजाति को इकाई लागत का 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

बकरी पालन मजदूर, सीमांत और लघु किसानों में काफी लोकप्रिय है। चाहे घरेलू स्तर पर 2-4 बकरी पालन हो या व्यवसायिक फार्म में दर्जनों, सैकड़ों या हजारों की तादाद में, इनकी देख-रेख और चारा पानी पर खर्च बहुत कम होता है। वैज्ञानिक तरीके से पालन करने से 4-5 माह में आमदनी शुरू हो जाती है। बकरी की प्रजाति का चुनाव स्थानीय वातावरण को ध्यान में रख कर करना चाहिए। कम बच्चे देने वाली या अधिक बच्चे देने वाली बकरियों से कमाई एक-सी ही होती है। उन्नत नस्ल की प्राप्ति के लिए बाहर से बकरा लाकर स्थानीय बकरियों के संपर्क में लाना चाहिए। आमतौर पर इसके लिए अप्रैल-मई और अक्टूबर-नवम्बर माह अनुकूल रहता है।

बाड़ा कैसे बनाएं

संभव हो तो बकरी का बाड़ा पूर्व से पश्चिम दिशा में ज्यादा फैला होना चाहिए। बाड़े की लंबाई की दीवार की ऊंचाई एक मीटर और उसके ऊपर 40-60 वर्ग फीट की जाली होना चाहिए। बाड़े का फर्श कच्चा और रेतीला होना चाहिए। रोग मुक्त रखने के लिए समय-समय पर चूने का छिड़काव करना चाहिए। जन्म के एक सप्ताह के बाद मेमने और बकरी को अलग-अलग रखना चाहिए। एक वयस्क बकरी को उसके वजन के अनुसार रोजाना एक से तीन किलोग्राम हरा चारा, आधा से एक किलोग्राम भूसा और डेढ़ से चार सौ ग्राम दाना रोजाना खिलाना चाहिए। बकरियों को साबुत अनाज और सरसों की खली नहीं खिलाना चाहिए। दाने में 60 प्रतिशत दला हुआ अनाज, 15 प्रतिशत चोकर, 15 प्रतिशत खली, 2 प्रतिशत खनिज तत्व और एक प्रतिशत नमक होना चाहिए। बकरियों को पीपीआर, ईटी खुरपका, गलघोंटू और चेचक के टीके जरूर लगवायें। यह टीके मेमनों को 3-4 माह की उम्र के बाद लगते हैं। साथ ही अंतःपरजीवी नाशक दवाइयां साल में दो बार जरूर पिलायें। अधिक सर्दी, गर्मी और बरसात से बचाने के इंतजाम करें। नवजात मेमने को आधे घंटे के भीतर बकरी का पहला दूध पिलाने से उसकी रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है।

जैविक कपास पर तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला, ग्वालियर कृषि विवि के कुलपति शुक्ला ने कहा

कपास मानव जीवन में प्रारंभ से अंत तक

खंडवा। कृषि महाविद्यालय द्वारा जैविक कपास पर अंतरराष्ट्रीय तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में देश विदेश के प्रतिभागी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े। शुभारंभ अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने अपने संबोधन में जैविक कपास पर आयोजित कार्यशाला पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इस क्षेत्र में ऐसे कार्यक्रमों से कृषकों को प्रोत्साहन मिलेगा कहा। अध्यक्षता करते हुए राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो.अरविन्द कुमार शुक्ला ने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान मानव की मूलभूत आवश्यकता है। कपास शिशु के तन को लंगोट के रूप में ढंकता है और अंत समय में यह मानव का कफन बनता है। कार्यक्रम में महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. आरआई सिसोदिया, पूर्व अधिष्ठाता डॉ. पीपी शास्त्री, डॉ. सतीश परसाई, डॉ. तनय जोशी, डॉ. डीके श्रीवास्तव, डॉ. डीके पालीवाल,डॉ. एसके अरसिया, कृषि संकाय डॉ. डीएच रानाडे, निदेशक अनुसंधान सेवाएं डॉ. संजय शर्मा, डॉ. एस मनिक्कम प्रमुख अन्वेषक (कपास विकास) आईसीएआर, सीआईसीआर कोयम्बतूर उपस्थित थे। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने जैविक कपास उत्पादन के लिए विकसित दो प्रजातियों राज विजय जैविक कपास एसजीएफ1 एवं एसजीएफ 2 को मध्य प्रदेश के लिए अनुकूल बताया।

अब स्वदेशी नैनो डीएपी भी तरल के रूप में बोतल में उपलब्ध होगी

किसानों को अब आधे दाम पर मिलेगी इफको की नैनो डीएपी

भोपाल/नई दिल्ली। जागत गांव हमार

आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कृषि क्षेत्र में नए अध्याय की शुरुआत हुई है। नैनो यूरिया के बाद खेती के लिए अब स्वदेशी नैनो डीएपी भी तरल के रूप में बोतल में उपलब्ध होगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गत दिनों इसका लोकार्पण किया। इस अवसर पर सहकारिता मंत्रालय के सचिव ज्ञानेश कुमार, इफको के चेयरमैन दिलीप संघानी और प्रबंध निदेशक यूएस अवस्थी भी उपस्थित थे। दानेदार डीएपी की तुलना में बोतल बंद डीएपी आधे से भी कम दाम पर मिलेगी। डीएपी की 50 किलो की परंपरागत बोरी की कीमत 1350 रुपये आती है, जबकि नैनो डीएपी की आधा लीटर की बोतल किसानों को छह सौ रुपये में उपलब्ध होगी। इसके प्रयोग से कृषि की लागत और आयात पर निर्भरता घटेगी।

विदेशी मुद्रा की बचत- नैनो डीएपी के प्रयोग से खेतों की सेहत सुधरेगी और पैदावार में भी वृद्धि होगी। साथ ही विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। दिल्ली के इफको भवन में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि नैनो डीएपी फर्टिलाइजर की फील्ड में भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा। केंद्र सरकार ने दो मार्च को ही अधिसूचित कर दिया है। इसके प्रयोग से खेत केमिकल मुक्त होगा। आधा लीटर की बोतल में नाइट्रोजन आठ एवं फास्फोरस 16 प्रतिशत है।

पहला संयंत्र गुजरात के कलोल में लगा

इफको को नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के लिए 20 वर्ष तक का पेटेंट मिला है। इसका पहला संयंत्र गुजरात के कलोल में लगा है। इस वर्ष पांच करोड़ बोतल का उत्पादन किया जाएगा। 2025-26 तक 18 करोड़ बोतल उत्पादन के माध्यम से 90 लाख टन डीएपी का बोझ कम होगा। एक वर्ष में ही नैनो यूरिया के तीन संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। इफको की उपलब्धि बताते हुए अमित शाह ने कहा कि देश में कुल 384 लाख टन उर्वरकों का उत्पादन हुआ है, जिसमें 132 लाख टन सहकारी समितियों ने किया। इनमें अकेले इफको ने 90 लाख टन उर्वरकों का उत्पादन किया है। उन्होंने कहा कि एक वर्ष के भीतर नैनो यूरिया के तीन संयंत्रों को चालू कर दिया गया है। अभी छह करोड़ तीन लाख बोतल की आपूर्ति की जा रही है। इससे यूरिया का आयात कम हुआ है। इफको अपनी कलोल इकाई में प्रति दिन आधा लीटर की दो लाख बोतलों की उत्पादन क्षमता के साथ एक नैनो डीएपी संयंत्र स्थापित कर रहा है।

तरल डीएपी खेती को संरक्षित करेगी

अमित शाह ने कहा कि देश में पारंपरिक डीएपी का ही अत्यधिक इस्तेमाल किया जाता है। पंजाब, हरियाणा, बंगाल एवं उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में प्रति एकड़ छह से आठ बोरे दानेदार डीएपी का इस्तेमाल किया जाता है। तमिलनाडु में धान की फसल में दानेदार डीएपी की टाप ड्रेसिंग की जाती है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक और बिहार के किसान मक्का, गन्ना एवं सब्जियों की खेती में भी धड़ल्ले से दानेदार डीएपी का प्रयोग करते हैं। नैनो डीएपी एवं नैनो यूरिया के प्रयोग से खेतों में केंचुओं की संख्या बढ़ेगी, जिससे भूमि को संरक्षित किया जा सकेगा।

आधा लीटर की बोतल 50 किलो डीएपी के बराबर

सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किसानों से नैनो डीएपी के इस्तेमाल का आह्वान करते हुए कहा कि आधा लीटर की नैनो डीएपी की बोतल 50 किलो की परंपरागत डीएपी की बोरी के बराबर काम करेगी। एक एकड़ खेत के लिए आधा लीटर की बोतल काफी है। उन्होंने कहा कि नैनो यूरिया को किसानों ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन अभी बोरी वाली यूरिया भी प्रयोग में है। इससे फसल और मिट्टी को नुकसान होता है। नैनो यूरिया के साथ दानेदार यूरिया की जरूरत नहीं है। इसका प्रयोग न करें।

बड़वानी के अतुल पाटीदार का पीएम मोदी ने 'मन की बात' में किया जिक्र

भोपाल। जागत गांव हमार

प्रदेश के बड़वानी जिले के अतुल पाटीदार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के जीवन को सरल और सुलभ बनाने के लिए सराहना की। इसके साथ ही पीएम मोदी का देशभर में लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात के 100वें एपिसोड के प्रसारण पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में अतिथि के रूप में आमंत्रित भी किया गया।

अतुल पाटीदार की ई-कॉमर्स कंपनी फार्मकार्ट है, जिसने कोरोना काल जैसे कठिन समय में किसानों को खेती-किसानी का सामान घर बैठे उपलब्ध कराया था। कोरोनाकाल में वैसे तो हर व्यक्ति अपनी रोजमर्रा के उपयोग में आने वाले सभी प्रोडक्ट को ऑनलाईन प्लेटफॉर्म से मंगा लेते थे, लेकिन खेती के उपयोग में आने वाले बीज-खाद और कीटनाशक जैसी महत्वपूर्ण वस्तुएं ऑनलाइन उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। कोरोना का समय था और उस लॉकडाउन के समय देश के हालात भी बदतर थे। पूरे देश के साथ किसान भी परेशानी में थे। कोरोना के समय हालात ही ऐसे थे की किसान क्या करें वो खेती कैसे करें जब उनके पास बीज-खाद और कीटनाशक ही नही थे। किसानों की इस समस्या को बड़वानी जिले के अतुल पाटीदार ने समझा। अतुल ने इस परेशानी को दूर करने के लिए एक ऐसी वेबसाइट और एप्लीकेशन डेवलप

किया, जिससे किसान बिना किसी परेशानी के घर बैठे ही खेती का सामान मंगा सकते हैं। अतुल के द्वारा चलाए गए इस ऐप ने किसानों की खेती से जुड़े कार्यों को कोरोना काल में भी सरल और सुलभ बना दिया था। मोदी ने अतुल पाटीदार का जिक्र पहले भी अपने 70वें एपिसोड में किया और अतुल और फार्मकार्ट कंपनी के उल्लेखनीय कार्यों की सराहना की थी।

कौन हैं अतुल पाटीदार

मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले के युवा उद्यमी अतुल पाटीदार एक किसान परिवार से आते हैं, जिन्होंने 2017 में अपने साथियों के साथ मिलकर किसानों के जीवन को सरल और सुलभ बनाने के लिए फार्मकार्ट कंपनी की शुरूआत की थी। अतुल विश्व के सर्वोत्तम विश्वविद्यालय से 4 स्नात्तकोतर की उपाधियां प्राप्त कर चुकें हैं। अतुल और फार्मकार्ट कंपनी पिछले 5 सालों से किसानों के खेती को सरल और सुविधाजनक बनाने का प्रयास कर रही हैं।

देश के छोटे किसानों को मिलें टेक्नालॉजी का लाभ

भोपा/नई दिल्ली। जागत गांव हमार

सीआईआई व ट्रैक्टर एंड मैकेनाइजेशन एसोसिएशन (टीएमए) द्वारा फार्म मशीनरी टेक्नालॉजी पर आयोजित शिखर सम्मेलन का शुभारंभ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। यहां तोमर ने कहा कि देश में लगभग 85 प्रतिशत छोटे किसान हैं, जिन्हें टेक्नालॉजी-मशीनरी का लाभ मिलना चाहिए। कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम) के तहत प्रशिक्षण, परीक्षण, सीएचसी, हाई-टेक हब, फार्म मशीनरी बैंकों (एफएमबी) जैसी विभिन्न गतिविधियों के लिए वर्ष 2014-15 से 2022-23 तक राज्यों को 6120.85 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। वहीं राज्य सरकारों के माध्यम से ट्रैक्टर, पावर टिलर और स्वचालित मशीनरी सहित सब्सिडी पर 15.24 लाख कृषि मशीनरी और उपकरण वितरित किए गए हैं। तोमर ने कहा कि भारत सरकार द्वारा केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान (सीएफएमटीआई), बुदनी (मप्र) में ट्रैक्टरों के परीक्षण की नई व्यवस्था लागू कर परीक्षण को पूरा करने की अधिकतम समय-सीमा को घटाकर अधिकतम 75 कार्य दिवस कर दिया गया है। साथ ही, वर्ष 2014-15 से 2022-23 तक केंद्र सरकार द्वारा अपने चार एफएमटीटीआई व चिन्हित नामित अधिकृत परीक्षण केंद्रों के माध्यम से 1.64 लाख प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया हैं। कार्यक्रम में सीआईआई व टीएमए के भारतेंदु कपूर, मुकुल वार्ष्णेय, जॉन डेर, कृष्णकांत तिवारी, एंटनी चेरूकारा सहित अन्य पदाधिकारी व सदस्यगण मौजूद थे।

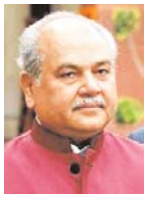

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक- **अरविंद मिश्र, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)